THE HINDU • MONDAY, MARCH 2, 2009

Go green with gusto!

FOOD Organic farming is the way forward

Organic farming is increasingly gaining attention from farmers as well as consumers. It is a form of agriculture that relies on crop rotation, green manure and biological pest control without the use of chemical fertilisers. Animal dung, crop residues, bio fertilisers from agro-industries and food processing units are some of the potential sources of nutrients of organic farming. With environmental awareness and concern increasing in general public, the mode of farming is gaining momentum.

M.R.Morarka-GDC Rural Research Foundation, which came into existence more than a decade ago, is a non-profit organisation helping the farmers to adopt organic farming. It came to Rajasthan as a blessing as this is a sprinkler-based system requiring very less water, ideal for a water-starved land. Its results are very much visible in the Shekhawati and other regions of the State, where the Foundation is active.

GO NATURAL Organic farming is gaining popularity

Organic products might be available off the shelf in our cities but there are a few myths which still need to be dispelled. Clearing the air, agriculture scientist Mukesh Gupta says, "The retailers make the cost of organic products high as the production is less than the consumption." He further adds, "The low-yielding organic agriculture systems are friendlier to the environment and more sustainable than high-yielding systems. Organic plant foods are far more beneficial to health than the conventional ones." Mukesh's point of view is corroborated by some farmers of Nawalgarh in the Shekhawati region , who believe that their productivity and profits have increased through organic farming. Khem Chand, who is practising this kind of farming for over a decade now, says, "Our crops are of very good quality and are sold at high prices. Now we do not have to spend money on costly pesticides. More and more farmers are adopting this method."

Organic farming has many benefits. Itreduces the level of pollution andhuman and animal health hazards by reducing the level of residue in the product. Such farming reduces the cost of agriculture production and also improves the soil health and the chemical and physical properties of the soil. Interestingly, Indian farmers were basically organic farmers before the advent of inorganic fertilisers and chemical pesticides.

No certification

Every farmer can choose and develop a suitable compost process depending upon his needs and resources. Kamal Morarka, a leading industrialist from Rajasthan and the founder of the Foundation, says, "For organic food we need the help of only the Central Government and that too for certification as there is no Indian company to issue certificates for organic products."

S.M. AAMIR

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली, मंगलवार, 24 मार्च, 2009

जरूरी है खेत और खेती में सुधार

मुद्दा

आशुतोष प्रताप सिंह

मुद्रास्फीति में भारी गिरावट के बावजूद वास्तविक महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल मुद्रास्फीति मापने के हमारे पैमाने सही नहीं हैं। वास्तविक महंगाई का सीधा संबंध कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच के संतुलन से है। इस संतुलन में जब-जब गतिरोध आएगा वास्तविक महंगाई में कमी नहीं आएगी। खाद्यान्न कम हो तो समुचित वितरण से भी समस्या हल नहीं हो सकती। आज ग्लोबल स्तर पर खाद्यान्न की कमी है। जो देश इस कमी को आयात-निर्यात के बेहतर प्रबंधन और समुचित वितरण के जरिए पूरी कर पा रहे हैं, वही देश कुछ बेहतर स्थिति में हैं। फिर यह तरीका भी उन्हें दूर तक नहीं ले जा सकता।

संकट से बचने का ही एक उपाय है कि बढ़ती आबादी के अनुरूप उत्पादन बढ़ाया जाए। खेत और खेती दोनों को प्रमुखता दी जाए। भारतीय संदर्भ में देखें तो खेती की हालत काफी बुरी है। विगत दस सालों में उत्पादन और उत्पादकता दोनों स्थिरता को प्राप्त हो गये है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में तो साफ-साफ खेती के क्षेत्र में पांव पसारती मंदी का जिक्र है। इधर खेती के क्षेत्र में न तो किसी नई तकनीक का प्रवेश हुआ है और न ही इसका विस्तार हो रहा है। हरित क्रांति की प्रक्रिया में गतिरोध आ गया है। हम जिस स्थाई विकास की बात कर रहे हैं उसे तभी पाया जा सकता है जब खेती और तकनीक से उसे जोड़ा जाए। किसान आयोग ने इस संबंध में सरकार के सामने 5 प्रस्ताव रखे थे जिन पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव हैं– जमीन की गुणवत्ता बढ़ाना, पानी का संचयन व संरक्षण करना, आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराना, फसलों में सुधार करना, किसानों को जीवन बीमा की सुविधा देना तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार कर कृषि बाजार को नियमित करना शामिल है।

सबसे पहले हमें हरित क्रांति का केंद्र बिंदु रहे हरियाणा-पंजाब-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांति की स्वर्णिम स्थिति को बरकरार रखने पर ध्यान देना चाहिए। यहां मिट्टी के लवणीकरण, भू जल स्तर में गिरावट, खर-पतवारों की अधिकता, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग जैसी समस्या व्यापक हो गई है। किसानों के आगे आज की प्रतिकूल कीमत व्यवस्था भी नकारात्मक स्थिति पैदा कर रही है। यहां पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल खेती को संरक्षण देना होगा। अनाज की नई किस्मों को आर्गेनिक खेती से जोड़ना होगा। इसमें पशुधन की भूमिका प्रमुखता से होगी। रासायनिक कीटनाशकों, खनिज प्रधान उर्वरकों और जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों की प्रजातियों के प्रयोग पर लगाम कस कर आर्गेनिक खेती पद्धति का लाभ उठाना जरूरी है। हमारे प्रयास यह भी होने चाहिए कि हम खेती की तकनीकों का प्रसार पूर्वी भारत और सूखा प्रभावित इलाकों में भी करें। उत्पादन की दृष्टि से पूर्वी भारत में काफी संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम ये सारे सोये हुए शेर हैं जिन्हें सिर्फ जगाने की जरूरत है। इस इलाके के एक बड़े हिस्से में मानसूनी वर्षा न सिर्फ पर्याप्त होती है बल्कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। यहां हमें ऐसी तकनीक आजमानी होगी जो वर्ना जल एवं भूजल को संयुक्त रूप से कृषि के लिए लाभकारी बनाएं। फसल पद्धति में भी गेहूं-चावल-मक्का तथा अन्य फसलों को मिश्रित कर इस तरह से लगाया जाए जो अच्छी पैदावार देने के साथ मिट्टी की गुणवत्ता को भी बरकरार रखे। खेती को हमें सेज की वर्तमान व्यवस्था से भी जोड़ कर देखने की जरूरत है। देश में अभी करीब 11.5 करोड़ खेती करने वाले परिवारों के पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है। किसानों की आमदनी का एकमात्र जरिया खेती ही है। ऐसे में सेज के गठन से अगर किसानों को जमीन बेचने की नौबत आए तो स्थिति बेहद भयानक हो जाएगी। जमीन के लिए उन्हें चाहे जितनी भी बड़ी कीमत दी जाए परंतु चंद दिनों में ही उनकी हालत दिहाड़ी मजदूर वाली हो जाएगी।

सरकार सेज की नीति पर आंखें मूंद नहीं चल सकती। इससे पहले किसानों के लिए साज यानी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाने की जरूरत है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षमता का आकलन और खेती योग्य जमीन कर संरक्षण हो। साज के गठन के लिए जरूरी होगा कि किसानों को भी वैसी सुविधाएं और रियायतें दी जाए जो कारपोरेट घरानों को सेज के गठन के लिए दी गईं। अनाज उत्पादन की क्षमता में अव्वल क्षेत्र इसके लिए अधिक मुफीद होंगे। सिंचाई की उन्नत व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं वहां जरूर हो। सारी सुविधाएं जब सामूहिक रूप से एक बड़े क्षेत्र के किसानों के लिए मौजूद होगी तो लागत मूल्यों में कमी आना तय है। किसानों को बाजार से भी परिचित कराने की जरूरत है। छोटे-छोटे किसान मैनेजमेंट के गुर सीखेंगे तो खुद-ब-खुद वे नकदी फसलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान देंगे। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में तेजी आएगी बल्कि किसान भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।